पी टैग: प्रारंभिक परीक्षा
एस टैग: प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन पेपर-2, खेल और मामले।

# Weigh-in Controversy at the Paris Olympics

# पेरिस ओलंपिक में वज़न-मापन विवाद

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में, विनेश फोगाट (भारतीय पहलवान) दूसरी बार वज़न कम करने में विफल रहीं, जिसके कारण वह स्वर्ण पदक मुकाबले में भाग नहीं ले पाईं, जिससे पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने की उनकी संभावना समाप्त हो गई। वज़न-मापन के समय उनका वज़न 100 ग्राम अधिक था।

## पेरिस ओलंपिक में वज़न-मापन विवाद क्या है?

- पृष्ठभूमि: पेरिस ओलंपिक में **50** किलोग्राम में स्विच करने से पहले वह हाल ही में **53** किलोग्राम वर्ग में भाग ले रही थीं ।
  - फोगाट का सामान्य वज़न लगभग 55-56 किलोग्राम है, जिसे उन्हें प्रतियोगिता के दिनों में कम कर 50 किलोग्राम तक करना पड़ता है।
  - अपने कठोर प्रशिक्षण के कारण, वह पहले से ही बेहद दुबली हैं और उनके शरीर में बहुत कम वसा बचा है।
- वज़न घटाने के तरीके: एथलीट आमतौर पर विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं-
  - निर्जलीकरण: पानी का सेवन कम करना और पानी का वज़न कम करने के लिये सॉना या स्वेट सूट का उपयोग करना।
  - आहार प्रतिबंध: कैलोरी का सेवन सीमित करना और कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार का सेवन करना।
  - व्यायाम: कैलोरी बर्न करने और तेज़ी से वज़न कम करने के लिये कठोर व्यायाम करना।

## पेरिस ओलंपिक 2024 में वज़न-मापन क्या है?

- वज़न मापने के **UWW** नियम: यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग **(UWW)** के ओलंपिक वज़न मापने के नियमों के अनुसार, पहलवानों को अपनी प्रतियोगिता की सुबह वज़न मापना होता है।
  - एथलीट को सभी प्रतियोगिता के दिनों में श्रेणी सीमा के बराबर या उससे कम वज़न मापना होता है। ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिताएँ दो दिनों में होती हैं, जिसके लिये दोनों दिनों में वज़न मापना होता है।
  - फोगाट ने पहले दिन वज़न माप लिया, लेकिन दूसरे दिन **50** किलोग्राम की सीमा को पूरा करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।
- वज़न माप में विफल होने के परिणाम: किसी भी दिन वज़न माप में विफल होने वाले एथलीट अयोग्य घोषित कर दिये जाते हैं और उन्हें बिना रैंक के अंतिम स्थान दिया जाता है, जब तक कि उन्हें पहले दिन चोट ना लगी हो ।
- चोट अपवाद: पहले दिन घायल हुए एथलीट को दूसरे वज़न माप से छूट प्रदान की जाती है और इस तरह के मामले में संबंधित एथलीट के परिणाम को बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन यदि उन्हें पहले दिन के बाद चोट लगती है तो ऐसे मामले में एथलीट का दूसरे वज़न माप में शामिल होना आवश्यक हो जाता है।
- ओलंपिक कुश्ती के लिये प्रारूप में बदलाव: वर्ष 2017 से पहले, प्रत्येक भार वर्ग में ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिताएँ एक ही दिन में होती थीं, जिसमें एथलीट केवल एक बार वज़न मापते थे। वर्ष 2017 में UWW ने निष्पक्षता और एथलीट सुरक्षा में सुधार के लिये दो दिवसीय प्रारूप में बदलाव किया, जिसके तहत एथलीट्स को प्रतियोगिता के दोनों दिन अपना वज़न दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया।

**पहले दिन वज़न सटीक होने के बाद किसी पहलवान का वज़न किलोग्राम में कैसे बढ़ सकता है?**

- पुनर्जलीकरण और रिकवरी: पहले दिन वज़न करने के बाद, पहलवान तरल पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट्स और कार्बोहाइड्रेट के साथ पुनर्जलीकरण एवं पुनःपूर्ति करते हैं, जिससे खोया हुआ अधिकांश वज़न वापस आ जाता है।
- वज़न घटाने की अस्थायी प्रकृति: निर्जलीकरण के माध्यम से खोया हुआ वज़न ज्यादातर पानी का वज़न होता है, जो सामान्य जलयोजन और खाने के बाद फिर से प्राप्त हो जाता है, जिससे दूसरे दिन वज़न बढ़ जाता है।
- प्रदर्शन पर प्रभाव: हालाँकि पुनर्जलीकरण ऊर्जा को बहाल करता है लेकिन वज़न में तीव्रता से होने वाला परिवर्तन प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। यदि इसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया जाता तो थकान, ऐंठन और कम सहनशीलता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- रणनीतिक लाभ: कुछ पहलवान प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिये वज़न में कटौती करते हैं और प्रतियोगिता के दिन अधिक वज़न बढा लेते है जिससे कम वज़न वाले प्रतिद्वंदियों के खिलाफ शक्ति और बढ़ जाती है।

नोट:
पेरिस ओलंपिक में, स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
भारत की पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कॉंस्य पदक जीता और नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक-2024 में भाला फेंक में रजत पदक जीता।

और पढ़ें: मनु भाकर ने जीता ओलंपिक कॉंस्य पदक, वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिये भारत की महत्त्वाकांक्षा

https://youtu.be/ZxP3-DAUFjM

कीवर्ड: Weight Cutting Regulations, Competitive Edge, Strategic Advantage, Weight Control Techniques, Health Risks, Fair Competition, Injury Exceptions, Rule Changes, Weigh-in Compliance, Ranking Consequences, UPSC, CSE, PYQ.वज़न घटाने के नियम, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, रणनीतिक लाभ, वज़न नियंत्रण तकनीक, स्वास्थ्य जोखिम, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, चोट अपवाद, नियम परिवर्तन, वज़न-इन अनुपालन, रैंकिंग परिणाम, यूपीएससी, सीएसई, विगत वर्ष के प्रश्न ।
विवरण: वज़न घटाने से तात्पर्य कम वज़न वर्ग के लिये अर्हता प्राप्त करने हेतु प्रतियोगिता से पहले शरीर के वज़न को तेज़ी से कम करने के अभ्यास से है।

---

पी टैग: रैपिड फायर
एस टैग: पी.आई.बी., रैपिड फायर करंट अफेयर्स, प्रारंभिक परीक्षा, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, विविध

# Fast Tracking BIMSTEC Free Trade Agreement

# BIMSTEC मुक्त व्यापार समझौते पर त्वरित क्रियान्वयन

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग **(BIMSTEC)** व्यापार शिखर सम्मेलन में **BIMSTEC मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर त्वरित गति से वार्ता की अपील की।

- उन्होंने व्यापार वार्ता समिति और व्यापार समुदाय से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने के लिये एक अधिमान्य/तरजीही व्यापार समझौते पर विचार करने का आह्वान किया।
- भारत का BIMSTEC देशों के साथ कुल व्यापार वर्ष 2023-24 में **44.32** बिलियन अमरीकी डॉलर था।
    - थाईलैंड इस ब्लॉक में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जिसका निर्यात **5.04** बिलियन अमरीकी डॉलर तथा आयात **9.91** बिलियन अमरीकी डॉलर था।
    - बांग्लादेश का स्थान दूसरे स्थान पर था, जिसका निर्यात **11.06** बिलियन अमरीकी डॉलर तथा आयात **1.84** बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिससे भारत के पक्ष में 9.22 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार संतुलन बना।

**BIMSTEC** मुक्त व्यापार समझौता **(FTA):**

- इस पर फरवरी 2004 में हस्ताक्षर किये गए थे।
- इसमें सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और आर्थिक सहयोग पर **FTA** पर वार्ता का प्रावधान शामिल है।
- BIMSTEC देशों ने फ्रेमवर्क समझौते के अनुसार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिये व्यापार वार्ता समिति का गठन किया।

- 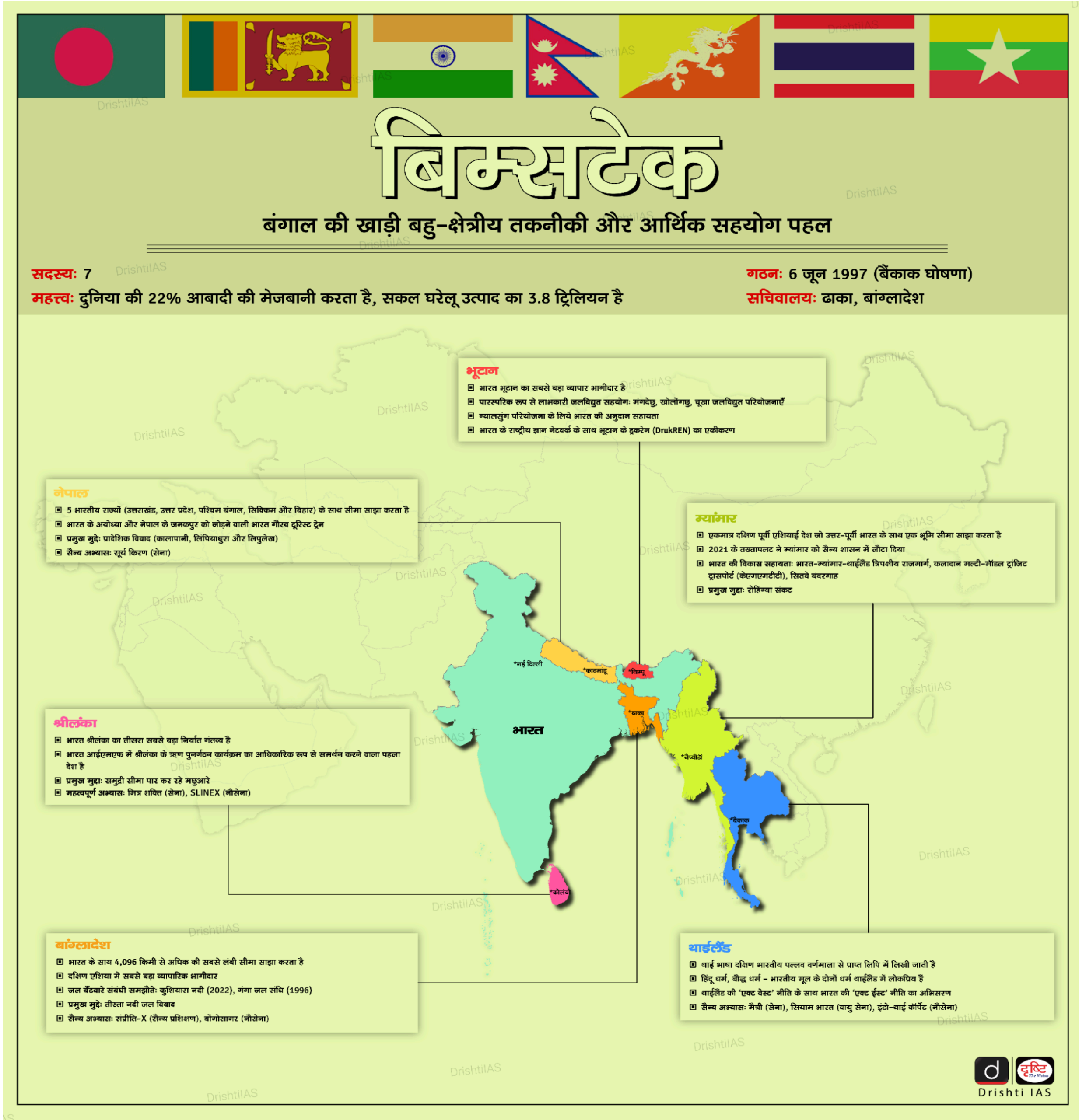


और पढ़ें: [BIMSTEC]

मेटा सर्च की-वर्ड्स: BIMSTEC, BIMSTEC Free Trade Agreement (FTA), BIMSTEC Business Summit, Preferential Trade Agreement, Trading Partner, Rapid Fire CA, UPSC, CSE, IAS, बिम्सटेक, बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), बिम्सटेक व्यापार शिखर सम्मेलन, तरज़ीही व्यापार समझौता, व्यापारिक भागीदार, रैपिड फायर करेंट अफेयर्स, यूपीएससी, सीएसई, आईएएस।

मेटा विवरण: भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) व्यापार शिखर सम्मेलन में BIMSTEC मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर त्वरित गति से वार्ता की अपील की।

---

पी टैग: रैपिड फायर
एस टैग: रैपिड फायर करेंट अफेयर्स, प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन पेपर- 1, भारतीय विरासत स्थल, भारतीय वास्तुकला

# Jaisalmer Fort

# जैसलमेर किला

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

राजस्थान के ऐतिहासिक जैसलमेर किले की दीवारें भारी बारिश के कारण ढह गईं, जिसके कारण इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बेहतर रखरखाव और संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। उचित रखरखाव के अभाव में दीवारें कमज़ोर होकर ढह गईं।

- जैसलमेर किला भारत का एकमात्र 'सक्रिय/जीवंत' किला है, जहाँ आज भी कई निवासी रहते हैं, जिससे इस किले का रखरखाव उनकी सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
  - राजा रावल सिंह द्वारा **1156 ई.** में निर्मित इस किले का निर्माण राज्य को आक्रमणों से बचाने के लिये रणनीतिक रूप से किया गया था। यह भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाले सिल्क रूट पर एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था।
    - सूर्य प्रकाश के कारण रंग बदलने वाले पीले बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला सुनहरा दिखाई देता है, जिसके कारण इसे "सोनार किला" या "स्वर्ण किला" नाम दिया गया है।
  - राज महल (रॉयल पैलेस) किले के भीतर सबसे बड़ा महल है, जिसमें अलंकृत बालकनियाँ हैं और इस किले में जटिल नक्काशी की गई है। यह मध्ययुगीन राजस्थानी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है जिसमें इस्लामी और राजपूत शैली के प्रभावों का एक उल्लेखनीय मिश्रण है।
- किले के रखरखाव के लिये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण **(ASI)** ज़िम्मेदार है।
- चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर किलों सहित राजस्थान के पहाड़ी किलों को वर्ष **2013** में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
  - जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ व रणथंभौर किलों के साथ प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष (राष्ट्रीय महत्त्व की घोषणा) अधिनियम, **1951** के तहत भारत के राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक के रूप में संरक्षित हैं।

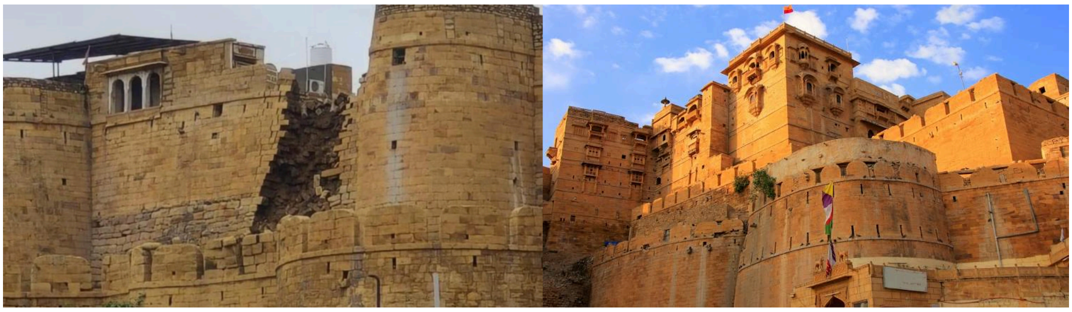

और पढ़ें: **MP के 6 नए स्थल और यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल**

**की-वर्ड्स:** Jaisalmer Fort Collapse, Sonar Quila Maintenance, UNESCO World Heritage Sites, Rajasthan Hill Forts, ASI Fort Preservation, Rapid Fire CA, UPSC, CSE, IAS. जैसलमेर किला पतन, सोनार किले का रखरखाव, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, राजस्थान पहाड़ी किले, ASI किला संरक्षण, रैपिड फायर करेंट अफेयर्स, यूपीएससी, सीएसई, आईएएस।
विवरण: राजस्थान में जैसलमेर किले की दीवार भारी वर्षा के कारण ढह गई, जिससे बेहतर रखरखाव और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता रेखांकित हुई।

पी टैग: प्रारंभिक परीक्षा
एस टैग: प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लिये त्वरित तथ्य, सामान्य अध्ययन- 2, स्वास्थ्य, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, सामान्य अध्ययन- 3

# Sucralose: A Promising Sweetener for Diabetics

# सुक्रालोज़: मधुमेह रोगियों हेतु एक आशाजनक मधुरक

स्रोत: द हिंदू

भारत में हाल ही में किये गए एक अध्ययन में टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के बीच सुक्रोज़ (टेबल शुगर) के विकल्प के रूप में गैर-पोषक मधुरक सुक्रालोज़ के उपयोग के संभावित लाभों पर प्रकाश डाला गया।

- यह अध्ययन गैर-मधुमेह रोगियों में वज़न नियंत्रण के लिये गैर-पोषक मधुरक (Non-Nutritive Sweeteners- NNS) के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल की चेतावनी के विपरीत है।

## अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या थे?

- अध्ययन में हस्तक्षेप और नियंत्रण समूहों के बीच रक्त ग्लूकोज़ नियंत्रण के प्रमुख संकेतक, ग्लूकोज़ या **HbA1c** के स्तर में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं पाया गया।
- सुक्रालोज़ का उपयोग करने वाले प्रतिभागियों के शरीर के वज़न, कमर की परिधि और बॉडी मास इंडेक्स **(BMI)** में मामूली सुधार देखा गया।
- सुक्रालोज़ का विवेकपूर्ण उपयोग समग्र कैलोरी और चीनी के सेवन को कम करने में मदद कर सकता है, जो मधुमेह के प्रभावी प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- महत्त्व: ये निष्कर्ष भारत के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जहाँ मधुरक का प्रयोग आम तौर पर कम होता है। अध्ययन से पता चलता है कि सुक्रालोज़ देश में मधुमेह रोगियों के लिये आहार अनुपालन में सुधार और वज़न प्रबंधन में सहायता कर सकता है।

## चीनी तथा चीनी के विकल्प क्या हैं?

- चीनी: यह फाइबर और स्टार्च के साथ कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। जबकि कार्बोहाइड्रेट हमारे स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, चीनी स्वयं आवश्यक नहीं है।
  - सफेद टेबल शुगर (चीनी), जिसे सुक्रोज़ के रूप में जाना जाता है, सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मधुरक है।
  - अन्य प्राकृतिक मधुरक में शामिल हैं: फ्रेक्टोज़, गैलेक्टोज़, ग्लूकोज़, लैक्टोज़, माल्टोज़।
- चीनी के विकल्प:
  - चीनी के विकल्प चीनी से जुड़ी कैलोरी के बिना मीठा स्वाद देते हैं, कुछ में बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती है।
  - वे आमतौर पर 'चीनी मुक्त', 'कीटो', 'कम कार्ब' या 'आहार' के रूप में लेबल किये गए उत्पादों में पाए जाते हैं।
- चीनी के विकल्प के प्रकार:
    - कृत्रिम मधुरक : इन्हें गैर-पोषक मधुरक (**NNS**) के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें मुख्य रूप से प्रयोगशालाओं में रसायनों से संश्लेषित किया जाता है, या प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से प्राप्त किया जाता है। ये टेबल शुगर की तुलना में 200 से 700 गुना अधिक मीठे हो सकते हैं।

- उदाहरण: एसेसल्फेम पोटेशियम (Ace-K), एडवांटेम, एस्पार्टेम, नियोटेम, सैकरीन, सुक्रालोज़ आदि।

- शुगर एल्कोहल: ये कृत्रिम रूप से चीनी से प्राप्त होते हैं और कई प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में उपयोग किये जाते हैं। ये कृत्रिम मधुरक की तुलना में कम मीठे होते हैं और च्युइंग-गम व हार्ड कैंडी जैसे उत्पादों को बनावट एवं स्वाद प्रदान करते हैं।
    - उदाहरण: एरिथ्रिटोल, आइसोमाल्ट, लैक्टिटोल, माल्टिटोल, सोर्बिटोल और ज़ाइलिटोल आदि।
- नोवेल मधुरक : ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार के मधुरक के लाभ प्रदान करते हैं। इनमें कैलोरी और मधुरकता कम होती है, जिससे वज़न और रक्त शर्करा में वृद्धि नहीं होती है तथा ये सामान्यतः कम प्रसंस्कृत होते हैं जो उनके प्राकृतिक स्रोतों से काफी मिलते जुलते हैं।
    - उदाहरण: एलुलोज़, मॉन्क फ्रूट, स्टीविया, टैगेटोज़ आदि।

## मधुमेह क्या है?

- परिचय:
    - मधुमेह या मधुमेह मेलेटस (DM) एक चिकित्सीय विकार है, जिसमें इंसुलिन का अपर्याप्त उत्पादन या इंसुलिन के प्रति असामान्य अनुक्रिया होती है, जिसके कारण रक्त शर्करा (ग्लूकोज़) का स्तर बढ़ जाता है।
    - जबकि 70–110 mg/dL रक्त ग्लूकोज़ (उपवास) को सामान्य माना जाता है, 100 से 125 mg/dL के बीच रक्त ग्लूकोज़ स्तर को प्री-डायबिटीज़ माना जाता है तथा **126 mg/dL** या इससे अधिक के ग्लूकोज़ स्तर को मधुमेह के रूप में परिभाषित किया गया है।

| मधुमेह के प्रकार | | |
|---|---|---|
| | टाइप **1** मधुमेह | टाइप **2** मधुमेह |
| कारण | इसमें अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, क्योंकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली लैंगरहैंस की द्विपिकाओं पर हमला करती है। | इसमें अग्नाशय कम इंसुलिन बनाता है और शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। |
| व्यापकता | टाइप **1** मधुमेह जिससे लगभग **5-10%** लोग प्रभावित हैं, आमतौर पर **30** वर्ष की आयु से पहले विकसित हो जाता है, हालाँकि यह इस उम्र के बाद भी विकसित हो सकता है। | टाइप 2 मधुमेह अधिक आम है, लेकिन यह आमतौर पर **30** वर्ष की आयु के बाद विकसित होता है और उम्र के साथ बढ़ता जाता है। |
| रोकथाम | इसकी रोकथाम नहीं की जा सकती। | जीवनशैली में बदलाव करके इसकी रोकथाम की जा सकती है। |

- मधुमेह से निपटने की पहल:
    - कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)।

○ विश्व मधुमेह दिवस
○ ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट

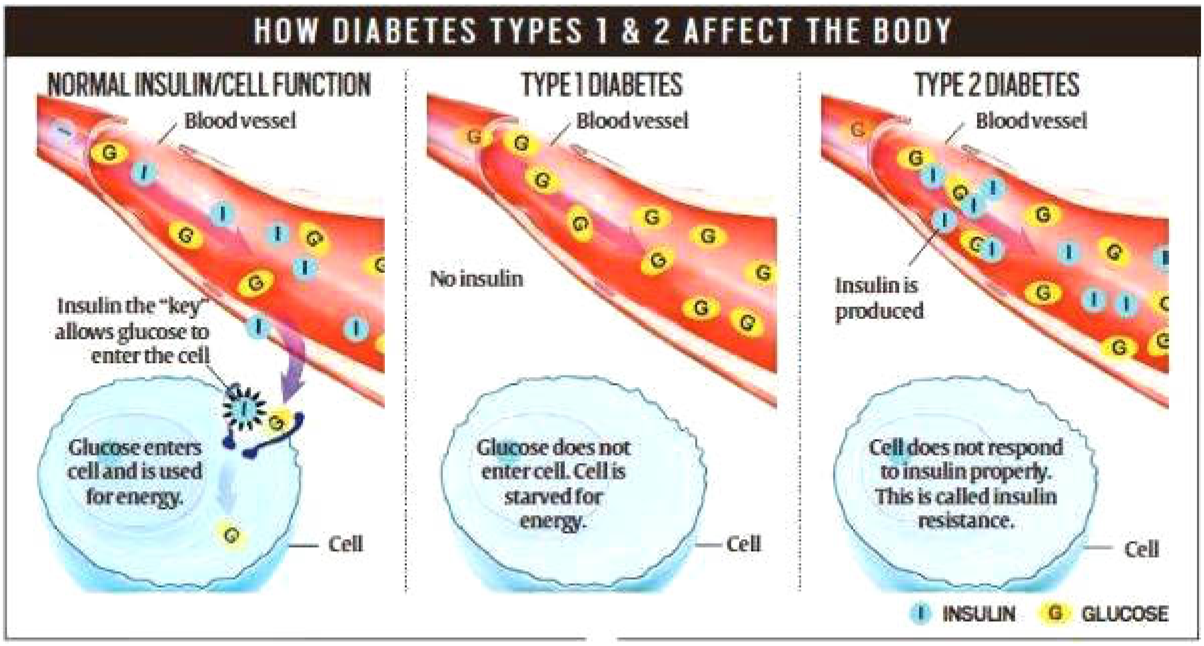


मेटा सर्च की-वर्ड्स: Sucralose, Sweeteners, Diabetes, Table Sugar, Body Mass Index (BMI), World Health Organization (WHO), Non-Nutritive Sweeteners (NNS), Artificial Sweeteners, UPSC, CSE, PYQ, सुक्रालोज़, मधुरक, मधुमेह, टेबल शुगर, बॉडी मास इंडेक्स (BMI), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), गैर-पोषक मधुरक (NNS), कृत्रिम मधुरक, यूपीएससी, सीएसई, विगत वर्ष के प्रश्न।

विवरण: भारत में हाल ही में किये गए एक अध्ययन में टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्तियों के बीच सुक्रोज़ (टेबल शुगर) के विकल्प के रूप में सुक्रालोज़, एक गैर-पोषक मधुरक के प्रयोग के संभावित लाभों को रेखांकित किया गया है।

---

पी टैग: भारतीय अर्थव्यवस्था
एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर- 2, स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएँ, विकास से संबंधित मुद्दे, सामान्य अध्ययन पेपर- 3, राजकोषीय नीति

# GST on Health and Life Insurance in India

# भारत में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST

प्रिलिम्स के लिये: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP), आयुष्मान भारत-PMJAY, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य बीमा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वस्तु एवं सेवा कर (GST)
मेन्स के लिये: भारत में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST, बीमा पर उच्च करों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना- चुनौतियाँ और आगे की राह, भारत में बढ़ी हुई स्वास्थ्य सेवा निधियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने से जुड़ी चुनौतियाँ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर, विशेष रूप से विपक्षी नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों के बाद बहस तेज़ हो गई है, जिसमें बीमा प्रीमियम पर **18% GST** को वापस लेने की मांग की गई।

- इस कर के कारण प्रीमियम की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे अनेक नागरिकों के लिये बीमा खरीदना अप्राप्य हो गया है, जिसके कारण संसद में तथा उद्योग के हितधारकों के बीच इस विषय पर चर्चा हुई है।

## भारत में स्वास्थ्य व्यय की वर्तमान स्थिति क्या है?

- उच्च चिकित्सा मुद्रास्फीति:
    - भारत का स्वास्थ्य देखभाल व्यय जाँच के दायरे में है, वर्ष 2023 के अंत तक चिकित्सा मुद्रास्फीति लगभग **14%** थी।
- उच्चतर आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय **(OOPE):**
    - राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा **(NHA)** के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 में कुल स्वास्थ्य व्यय **(THE)** का आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) अभी भी लगभग 39.4% है।
    - हालाँकि यह वर्ष **2014-15** में **62.6%** से घटकर वर्ष **2021-22** में **39.4%** हो गया था।
    - उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में OOPE 71.3% तक था।
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय **(GHE)** में मामूली वृद्धि**:**
    - कुल स्वास्थ्य व्यय **(THE)** में सरकारी स्वास्थ्य व्यय **(GHE)** की हिस्सेदारी वर्ष **2013-14** में **28.6%** से बढ़कर वित्त वर्ष **2019** में केवल **40.6%** हो गई है।
    - सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में **GHE 2014-15** से **2021-22** के दौरान 63% बढ़ा, जो वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के **1.13%** से बढ़कर वर्ष **2021-22** तक **1.84%** हो गया।
    - 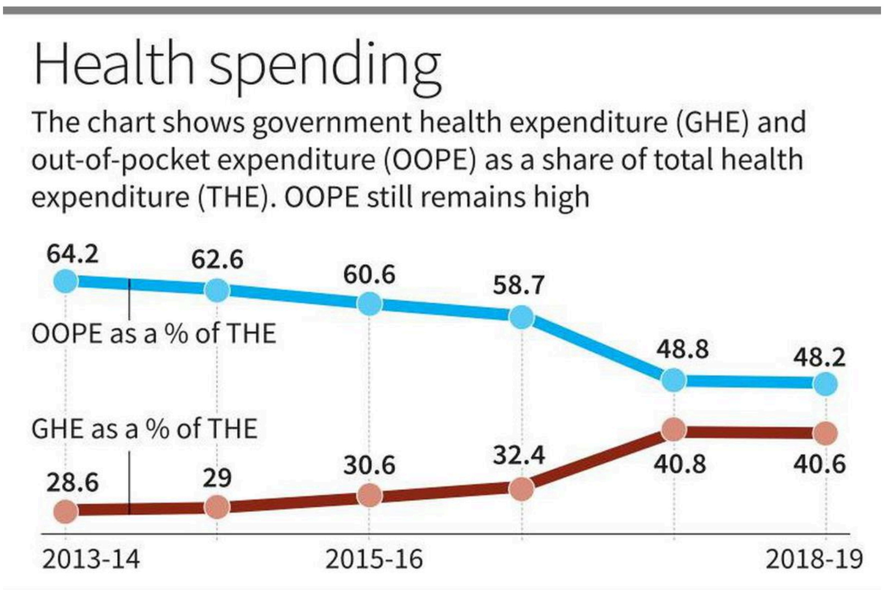

- सकल घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा: वर्ष 2019-20 में, भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) 6,55,822 करोड़ रुपए अनुमानित था, जो सकल घरेलू उत्पाद का **3.27%** और प्रति व्यक्ति 4,863 रुपए है।
  - तुलनात्मक रूप से, अमेरिका जैसे देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग **18%** हिस्सा स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय करते हैं, जबकि जर्मनी और फ्राँस जैसे देश लगभग **11-12%** व्यय करते हैं।

## स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर **GST** कम करने की आवश्यकता क्यों है?

- बीमा एक बुनियादी आवश्यकता: बीमा एक मूलभूत आवश्यकता है क्योंकि यह अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, परिवार के वित्तीय हितों की रक्षा करता है। इस प्रकार इस पर उच्च कर नहीं लगाया जाना चाहिये।
- वहनीयता: बीमा प्रीमियम पर 18% GST के कारण पॉलिसी-धारकों के लिये लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ मामलों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 50% तक की वृद्धि होने के कारण, कई व्यक्तियों के लिये अपनी पॉलिसी को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है।
- वैश्विक तुलना: भारत में बीमा पर GST विश्व में सबसे अधिक है। सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग जैसे देश बीमा पर इस तरह का कर नहीं लगाते हैं, जिससे उनके बीमा उत्पाद अधिक आकर्षक और किफायती हो जाते हैं।
- बीमा प्रीमियम पर प्रभाव: उच्च GST दर भारत में बीमा प्रीमियम को कम करने में योगदान देती है, जो वर्ष **2022-23** में केवल **4%** थी, जो वैश्विक औसत लगभग **7%** से कम है।
  - GST को कम करने से अधिक लोग बीमा खरीदने हेतु प्रोत्साहित हो सकते हैं, जो "वर्ष **2047** तक सभी के लिये बीमा" के लक्ष्य के अनुरूप होगा।
- आर्थिक विकास: बीमा प्रीमियम पर कर लगाने से बीमा क्षेत्र का विकास बाधित हो सकता है, जो आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण है।

## जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर **GST** हटाने के क्या नुकसान हो सकते हैं?

- सरकारों के लिये राजस्व हानि: जीवन और स्वास्थ्य बीमा से GST के कारण (@ 18%) संघीय और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। इसे हटाने से बजट घाटा हो सकता है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों और सेवाओं के लिये धन प्रभावित हो सकता है।
- अन्य करदाताओं पर बोझ बढ़ सकता है: राजस्व क्षति की भरपाई के लिये, सरकारों को करदाताओं पर भारी बोझ डालते हुए अन्य करों को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।
- बढ़ी हुई कीमतों की संभावना: GST हटाने से उपभोक्ताओं के लिये लागत कम हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता राजस्व के स्तर को बनाए रखने के लिये कीमतें बढ़ा सकते हैं जिससे इच्छित लाभ में कमी आ सकती है।

## भारत का बीमा और पेंशन क्षेत्र: विकास का अवसर

- वैश्विक तुलना और विकास के अवसर:
  - भारत के बीमा और पेंशन क्षेत्र अपने वैश्विक समकक्षों से पीछे हैं। जबकि ये क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः **19%** और **5%** का योगदान करते हैं, अमेरिका **(52%** और **122%)** और यू.के. **(112%** और **80%)** जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएँ काफी अधिक योगदान को दर्शाती हैं।
    - यह अंतर भारत के बीमा और पेंशन बाज़ार में वृद्धि के लिये पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करता है।
- उद्योग प्रदर्शन:

- सामान्य बीमा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अकेले स्वास्थ्य प्रीमियम से **1,09,000** करोड़ रुपए एकत्र किये।
- जीवन बीमा उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में प्रीमियम से 3,77,960 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें **LIC** का योगदान सबसे अधिक 2,22,522 करोड़ रुपए रहा।

Health insurance

| Class of business | No. of policies (in lakh) | | No. of lives (in lakh) | | Gross premium (in ₹ crore) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 |
| Government sponsored | 0.001 | 0.001 | 3,429 | 3,065 | 4,290 | 6,076 |
| Group | 9.1 | 7 | 1,187 | 1,623 | 28,108 | 36,891 |
| Individual | 228.3 | 219.3 | 531 | 516 | 25,840 | 30,085 |
| Total | 237.4 | 226.3 | 5,147 | 5,204 | 58,238 | 73,052 |

Source: Standing Committee Report

## आगे की राह

- **GST** समीक्षा: सरकार को स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिये ताकि उन्हें अधिक किफ़ायती बनाया जा सके तथा उच्च निवेश दर को प्रोत्साहित किया जा सके।
  - पूर्व वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने प्रीमियम कम करने और पॉलिसी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिये स्वास्थ्य तथा टर्म बीमा पर GST घटाने का प्रस्ताव दिया है।
- बीमा क्षेत्र को पूंजी सहायता: संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बीमा क्षेत्र की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 'ऑन-टैप' बॉण्ड जारी करे, जिसकी अनुमानित राशि 40-50,000 करोड़ रुपए है।
  - 'ऑन-टैप बॉण्ड' से तात्पर्य ऐसे बॉण्ड से है जो किसी विशिष्ट पेशकश या नीलामी में जारी किये जाने के बजाय किसी भी समय खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा में अधिक सार्वजनिक निवेश: विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि से पता चलता है कि अधिक व्यय से सेवाओं का अधिक उपयोग होता है। जैसे-जैसे स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती होती जाती है, अव्यक्त मांग स्पष्ट होती है, जिससे अधिक लोग स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठा पाते हैं।
- अधिक मेडिकल कॉलेजों में निवेश: यह सिफारिश की जाती है कि अन्य चिकित्सा संस्थानों में निवेश किया जाए, ताकि संभावित रूप से व्यय में कमी लाई जा सके, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जा सके, न कि केवल कुछ अपवादात्मक क्षेत्रों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाए, जैसा कि एम्स करता है।

- नीति सुधार: चिकित्सा मुद्रास्फीति को कम करने और स्वास्थ्य सेवा लागत को नियंत्रित करने हेतु नीति सुधार स्वास्थ्य बीमा सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बीमाकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने से प्रतिस्पर्द्धा और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे लागत में और कमी आएगी।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

और पढ़ें: भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिये कोई आयु सीमा नहीं

## यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

**मेन्स**

**प्रश्न. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता होने के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना सतत् विकास के लिये एक आवश्यक पूर्व शर्त है" विश्लेषण कीजिये। (2021)**

कीवर्ड: Goods and Services Tax (GST), Medical Inflation, Higher Out-of-Pocket Expenditure (OOPE), Government Health Expenditure, GDP, Economic Growth, Economic Development, UPSC, CSE, PYQ.वस्तु और सेवा कर (GST), चिकित्सा मुद्रास्फीति, उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE), सरकारी स्वास्थ्य व्यय, GDP, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, यूपीएससी, सीएसई, विगत वर्ष के प्रश्न।
विवरण: स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लेकर बहस ने हाल ही में गति पकड़ी है, विशेष रूप से विपक्षी नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बाद, जिसमें बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग की गई है।

---

पी टैग: रैपिड फायर
एस टैग: रैपिड फायर करेंट अफेयर्स, प्रारंभिक परीक्षा, विविध, विश्व इतिहास

# Discovery of Cult Temple in Italy

# इटली में पंथ मंदिर की खोज

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

हाल ही में पुरातत्वविदों ने इटली के टस्कनी में सासो पिनज़ुटो नेक्रोपोलिस में प्राचीन एट्रस्केन सभ्यता से संबंधित **2,700** वर्ष पुराना एट्रस्केन पंथ मंदिर (या ओइकोस) खोजा है।

- उन्होंने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर हेलेनिस्टिक काल **(323-31** ईसा पूर्व**)** तक के 120 से अधिक कक्षीय कब्रों की खोज की।

इट्रस्केन सभ्यता:

- यह मध्य इटली (आठवीं से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) में तिबर **(Tiber)** और आर्नो **(Arno)** नदियों के बीच तथा एपेनिन पर्वतों **(Apennine Mountains)** के पश्चिम और दक्षिण में फली-फूली।
- यह सभ्यता, एक साझा भाषा और संस्कृति से एकजुट शहर-राज्यों का एक संघ था, जिसका उत्तरोत्तर रोमन सभ्यता पर बहुत प्रभाव पड़ा।

एट्रस्केन मंदिर:

- एट्रस्केन मंदिर (Etruscan temples), जो आमतौर पर आयताकार होते थे, टफैसियस ओपस क्वाड्रेटम नींव (वर्गाकार कटे हुए टफ, एक नरम ज्वालामुखीय चट्टान से बने ठोस आधार) पर बनाए गए थे।
- महत्त्वपूर्ण दृश्यता और प्रतीकात्मक कारणों से इन्हें अक्सर जमीन से ऊँचाई पर रखा जाता था, ये मंदिर आमतौर पर शवादान स्थलों के पास होते थे, जो उन्हें अंत्येष्टि प्रथाओं से जोड़ते थे।
- धार्मिक और उत्सव के दृश्यों को दर्शाती उभरी हुई बहुरंगी मिट्टी की पट्टियाँ एक सामान्य सजावटी विशेषता थी।

और पढ़ें: हेलेनिस्टिक दर्शन

की-वर्ड्स: Etruscan Cult Temple, Oikos, Hellenistic period, Sasso Pinzuto necropolis, Tiber, Arno, Apennine mountains, UPSC, CSE, PYQ. एट्रस्केन पंथ मंदिर, ओइकोस, हेलेनिस्टिक काल, सासो पिनज़ुटो नेक्रोपोलिस, तिबर, आर्नो, एपेनिन पर्वत, यूपीएससी, सीएसई, विगत वर्ष के प्रश्न।
विवरण: हाल ही में पुरातत्वविदों ने इटली के टस्कनी में सासो पिनज़ुटो नेक्रोपोलिस में एक एट्रस्केन पंथ मंदिर (जिसे ओइकोस भी कहा जाता है) की खोज की है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह लगभग 2,700 वर्ष पुराना है।

---

प्रारंभिक परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन पेपर-1, वन संसाधन, संसाधनों का संरक्षण, महत्त्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएँ, ज्वालामुखी

## Wildfires Triggering Pyrocumulonimbus Clouds
## वनाग्नि के कारण उष्ण-कपासी वर्षा मेघ का विरचन

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हुई तीव्र वनाग्नि से उष्ण-कपासी वर्षा मेघ (पाइरो-क्यूमुलो-निम्बस बादल: **pyroCbs**) बन गए, जिनमें भीषण गर्जना और अधिक अग्नि प्रज्ज्वलित करने की क्षमता है।

## उष्ण-कपासी वर्षा (पाइरो-क्यूमुलो-निम्बस) मेघ क्या हैं?

- **परिभाषा:** पाइरो-क्यूमुलो-निम्बस बादल पृथ्वी की सतह से अत्यधिक ऊष्मा द्वारा निर्मित गर्जन वाले बादल हैं। इन्हें अग्निछाया या अग्नि मेघ भी कहा जाता है।
  - ये **कपासी वर्षा मेघ (Cumulonimbus Clouds)** के समान ही बनते हैं, लेकिन तीव्र ऊष्मा के परिणामस्वरूप जो प्रबल अपड्राफ्ट (मेघ का निर्माण) होता है, वह या तो भीषण वनाग्नि या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है।
- **इसके विरचन के लिये परिस्थितियाँ:**
  - उष्ण-कपासी वर्षा (पाइरो-क्यूमुलो-निम्बस) मेघ अत्यधिक ऊष्मा (जैसे वनाग्नि) के कारण बनते हैं।
    - प्रत्येक वनाग्नि से ये बादल नहीं बनते, तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिये, जैसा कि वर्ष 2019-2020 में ऑस्ट्रेलिया में लगी वनाग्नि में देखा गया था।
  - आग की तीव्र गर्मी से गर्म वायु तीव्रता से ऊपर की ओर उठती है, जिससे राख, धुआँ और जल वाष्प निकलती है, जो ठंडा होने पर पाइरोक्यूम्यलस बादलों में संघनित हो जाती है।
  - ये बादल **50,000** फीट तक पहुँच सकते हैं और तड़ित और तीव्र वायु के साथ गरज के साथ वर्षा करते हैं।
- **प्रभाव और विशेषताएँ:**
  - पाइरो-क्यूमुलो-निम्बस मेघ तड़ित उत्पन्न कर सकते हैं जो कई किलोमीटर दूर नई वनाग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं।
  - वे आम तौर पर कम वर्षा करते हैं, जिससे वनाग्नि के शमन के बजाय फैलने में मदद मिलती है।
  -

- ये बादल तेज़ वायु को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे वनाग्नि का प्रबंधन तेज़ और जटिल हो जाता है।

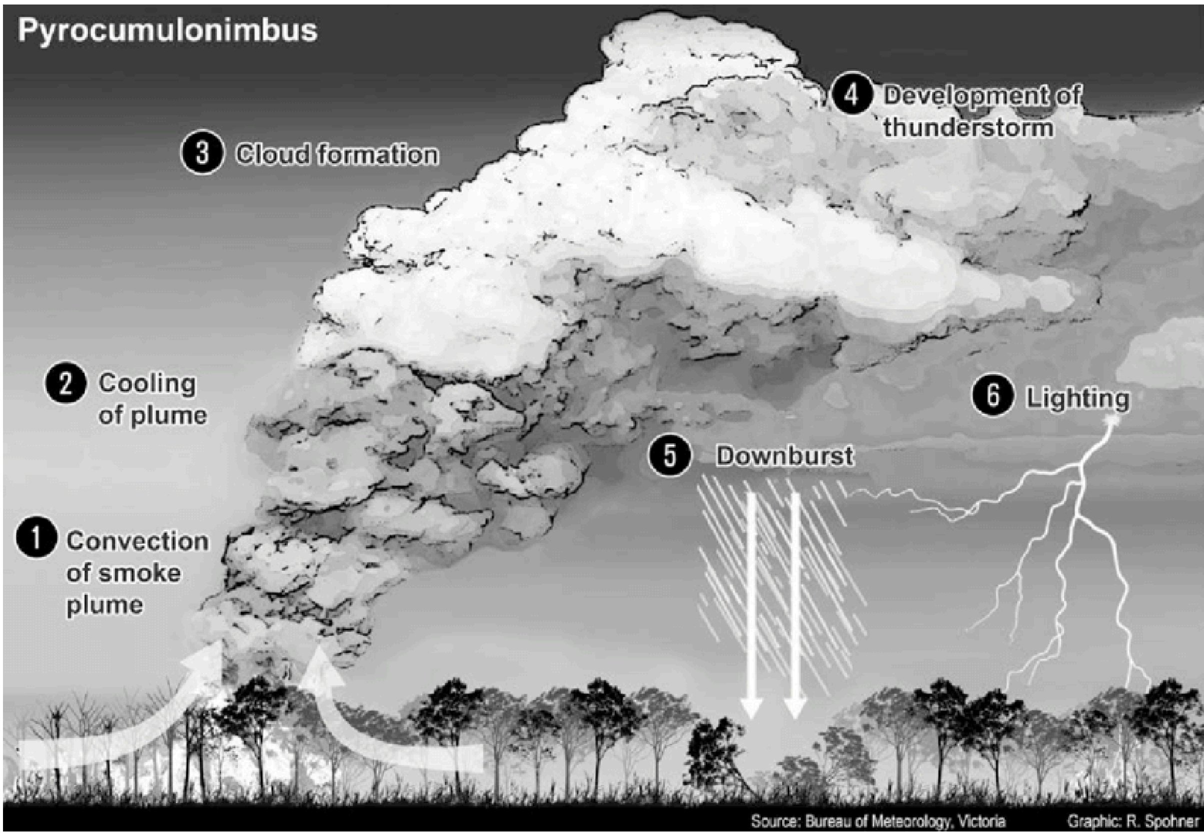


## उष्ण-कपासी वर्षा मेघ घटनाओं की आवृत्ति अधिक बार क्यों हो रही हैं?

- बढ़ता तापमान और विस्तारित फायर सीज़न: ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ता है और शुष्क अवधि लंबी होती है, जिससे शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न  होती हैं, जिससे वनाग्नि की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है तथा उष्ण-कपासी वर्षा मेघ निर्माण के लिये अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं।
- वनस्पति में वृद्धि और अनावृष्टि की स्थिति: उष्ण तापमान और बदलते वर्षा प्रतिरूप से वनस्पति में वृद्धि होती है, जो वनाग्नि के लिये ईंधन के रूप में कार्य करती है।
  - इसके अतिरिक्त, लगातार अनावृष्टि के कारण वन और घास के मैदान सूख जाते हैं, जिससे उनमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है।
- चरम मौसम पैटर्न: तीव्र और निरंतर हीट वेव के साथ-साथ परिवर्तित वायु पैटर्न के कारण वनाग्नि की घटना हो सकती है और यह तेज़ी से फैल सकती है, जिससे उष्ण-कपासी वर्षा मेघ बनने की संभावना बढ़ जाती है।
- मानवीय गतिविधियाँ: निर्वनीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन और शहरीकरण मानव-जनित आग की संभावना को बढ़ाकर तथा अप्रत्यक्ष रूप से उष्ण-कपासी वर्षा मेघ निर्माण में योगदान देकर वनाग्नि के जोखिम को बढ़ाते हैं।

और पढ़ें: वनाग्नि: एक गंभीर चिंता

https://youtu.be/I_Qh8NauQSU

## UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: **(2019)**

1. कार्बन मोनोऑक्साइड
2. मीथेन
3. ओज़ोन
4. सल्फर डाइऑक्साइड

उपरोक्त में से कौन फसल/बायोमास अवशेषों को जलाने के कारण वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं**?**

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: **(d)**

की-वर्ड्स**:** Geography, Important Geographical Phenomenons, Volcanoes, Wildfires, Forest Resources, Conservation of Resources, UPSC, CSE, PYQ  भूगोल, महत्त्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएँ, ज्वालामुखी, वनाग्नि, वन संसाधन, संसाधनों का संरक्षण, यूपीएससी, सीएसई, विगत वर्ष के प्रश्न

विवरण: संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हुई वनाग्नि इतनी तीव्र है कि इससे उष्ण-कपासी वर्षा मेघ (पाइरो-क्यूमुलो-निम्बस बादल: pyroCbs) बन गए हैं, जिनमें भीषण गर्जना और अधिक अग्नि प्रज्ज्वलित करने की क्षमता है।

---

पी टैग: रैपिड फायर
एस टैग: रैपिड फायर करेंट अफेयर्स, प्रारंभिक परीक्षा, विविध

# Ban on SIMI Extended

# SIMI पर प्रतिबंध बढ़ा

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

एक न्यायिक अधिकरण ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया **(SIMI)** पर लगाए गए प्रतिबंध को पाँच वर्ष के लिये बढ़ा दिया है।

- इसमें कहा गया है कि संगठन ने इस्लाम के लिये 'जेहाद' के अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा है और यह भारत में इस्लामी शासन की स्थापना हेतु कार्य करना जारी रखेगा।
- उक्त अधिकरण का गठन विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम **(UAPA), 1967** के तहत किया गया था।

    - UAPA का उद्देश्य भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना तथा उनका मुकाबला करना है।
- UAPA के प्रावधानों के तहत SIMI को "गैरकानूनी संगठन" घोषित करने की सिफारिश **10** राज्य सरकारों ने की है।
- SIMI को पहली बार वर्ष **2001** में गैरकानूनी घोषित किया गया था और तब से प्रतिबंध को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
- SIMI की स्थापना **25** अप्रैल **1977** को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जमात-ए-इस्लामी-हिंद **(JEIH)** से जुड़े एक युवा समूह के रूप में की गई थी, जो वर्ष **1993** में स्वतंत्र हो गया।

और पढ़ें: गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम का आकलन

की-वर्ड्स: Students Islamic Movement of India (SIMI), Tribunal, Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, Aligarh Muslim University, Rapid Fire CA, UPSC, CSE, IAS. स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI), ट्रिब्यूनल, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रैपिड फायर करेंट अफेयर्स, यूपीएससी, सीएसई, आईएएस।
विवरण: एक न्यायिक अधिकरण ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगाए गए प्रतिबंध को पाँच वर्ष के लिये बढ़ा दिया है।

---

पी टैग: भारतीय अर्थव्यवस्था
एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-3, बैंकिंग क्षेत्र और NBFC, संसाधनों का जुटाना

# NARCL Aims to Acquire Rs 2 Trillion Stressed Assets by FY26

# दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण का लक्ष्य

प्रिलिम्स के लिये: नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, बैड बैंक, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ, इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड
मेन्स के लिये: बैड बैंक का महत्त्व और संबंधित चुनौतियाँ, अशोध्य ऋण।

स्रोत: लाइव मिंट

## चर्चा में क्यों?

सरकार समर्थित बैड बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड **(NARCL)** ने वित्त वर्ष **2025-26** तक **2** ट्रिलियन रुपए की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

- यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों **(NPA)** के मुद्दे को हल करने के लिये एक सक्रिय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए वित्त वर्ष **2023-24** में **1** ट्रिलियन रुपए मूल्य की आपात परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के बाद है।

## बैड बैंक क्या है?

- परिचय: बैड बैंक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ हैं जो वाणिज्यिक बैंकों से अशोध्य ऋणों को खरीदती हैं, उनका प्रबंधन करती हैं और उनकी वसूली करती हैं तथा हस्तांतरित परिसंपत्तियों को नष्ट करने हेतु **NPA** का प्रबंधन करती हैं।

    - यह बैंकों के लिये एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जिससे उन्हें अशोध्य ऋणों को हटाने तथा ऋण देने की व्यवहार्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
- विकास: बैड बैंकों की अवधारणा 1980 के दशक में ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक जैसी संस्थाओं के साथ उभरी, जिन्होंने मेलॉन बैंक से अशोध्य परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया।
    - वर्ष **2008** के वित्तीय संकट के दौरान इस अवधारणा को प्रमुखता मिली। स्वीडन, जर्मनी और फ्राँस जैसे देशों ने अशोध्य परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिये इसी तरह के मॉडल लागू किये हैं।
    - भारत का पहला बैड बैंक, **NARCL** की स्थापना वर्ष **2021** में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशोध्य परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिये की गई थी। हालाँकि इस अवधारणा का प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षण **2016** में दिया गया था।
        - यह कदम आपात ऋणों के बोझ से दबी वित्तीय प्रणालियों को स्थिर करने हेतु अशोध्य बैंकों का उपयोग करने की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है।
- लाभ: बैड बैंक **NPA** के प्रबंधन को केंद्रीकृत करते हैं, जिससे प्रयासों में सरलता आती है और परिसंपत्ति समाधान में दक्षता बढ़ती है।
    - NPA को बैड बैंक में स्थानांतरित करके, मूल बैंक इन परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान के रूप में वर्तमान में रखी गई पूंजी को मुक्त कर सकते हैं। इससे संभावित रूप से अधिक ऋण योग्य ग्राहकों को ऋण देने में वृद्धि हो सकती है।
    - बैड बैंकों को सरकारी समर्थन मिलने से मूल बैंकों में विश्वास बढ़ सकता है, जिससे उनके समग्र पूंजी भंडार और वित्तीय स्थिरता में सुधार हो सकता है।
- हानि: अशोध्य परिसंपत्तियों को सरकार समर्थित इकाई को हस्तांतरित करने से केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर बोझ बढ़ेगा, जिससे होने वाले किसी भी हानि के लिये करदाता की देनदारी बढ़ सकती है।
    - सरकारी राहत पैकेज/ गवर्नमेंट बेलआउट बैंकों को अपने ऋण देने की पद्धतियों में सावधानी बरतने से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे भविष्य में ऐसी ही समस्याओं की पुनरावृत्ति हो सकती है।
- बैड बैंकों के लिये वर्तमान चुनौतियाँ:
    - मूल्य निर्धारण: बैड बैंकों को अक्सर अशोध्य ऋणों का मूल्य निर्धारण करने और भविष्य की देनदारियों का निर्धारण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
    - खरीदार ढूँढना: आपात परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो को बेचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से स्थापित बाज़ार तंत्र या पद्धति के बिना।
        - कमज़ोर आर्थिक स्थिति से परिसंपत्ति मूल्य में और गिरावट आ सकती है तथा संभावित खरीदारों की संख्या कम हो सकती है।

## NARCL क्या है?

- परिचय: 'बैड बैंक' के रूप में स्थापित किये गए NARCL का उद्देश्य विपत्तिकालीन/आपात ऋणों की वित्तीय प्रणाली की कमियों को दूर करना है, जिससे बैंकों को स्थिर किया जा सके और एक स्वस्थ आर्थिक वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके।
    - 500 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े ऋणों का प्रबंधन करने के लिये केंद्रीय बजट सत्र **2021-22** में **NARCL** की घोषणा की गई थी। प्रस्तावित संरचना से भारतीय रिजर्व बैंक के असंतुष्ट होने के कारण प्रारंभ में विलंब हुआ, जिसके कारण एक संशोधित योजना बनाई गई।
        - नई संरचना के तहत **NARCL** बैंकों से अशोध्य ऋण खातों का अधिग्रहण और एकत्रीकरण करता है। इंडिया डेट रेज़ॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड **(IDRCL)** NARCL के साथ एक विशेष व्यवस्था के तहत काम करते हुए समाधान/रेज़ॉल्यूशन प्रक्रिया का प्रबंधन करती है।
- **NARCL** की भूमिका: वाणिज्यिक बैंकों से अशोध्य ऋण का क्रय करना तथा इन आपात आस्तियों/परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना।
    - धन की वसूली और अंतरित परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने के लिये बोली लगाने की स्विस चैलेंज जैसी विधियों के माध्यम से उनका बाज़ार में विक्रय करना।
- वित्त पोषण और स्वामित्व: NARCL की अधिग्रहण रणनीति में सहमत ऋण मूल्य का **15%** नकद में और शेष **85%** सरकार द्वारा समर्थित प्रतिभूति प्राप्तियों में भुगतान करना शामिल है।
    - **NARCL** में सरकारी बैंकों की **51%** हिस्सेदारी है, जबकि शेष हिस्सेदारी निजी बैंकों के पास है।
- **NARCL** के समक्ष चुनौतियाँ:
    - दोहरी संरचना के मुद्दे: NARCL और IDRCL की द्वैधता ने परिचालन अक्षमताओं को जन्म दिया है। NARCL के पास निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन IDRCL समाधान/विक्रय करता है, जिससे एक जटिल और महंगी संरचना बनती है।

    - मूल्य निर्धारण विसंगतियाँ: NARCL और बैंकों के बीच मूल्य निर्धारण अपेक्षाओं में बड़े अंतर ने लेन-देन को रोक दिया है, क्योंकि बैंकों को **NARCL** के प्रस्ताव अपर्याप्त लगते हैं।
    - उच्च परिचालन लागत: NARCL व IDRCL दोनों की आवश्यकता के परिणामस्वरूप परिचालन लागत में वृद्धि हुई है, जो **NARCL** की बाह्य सलाहकारों पर निर्भरता एवं धीमी प्रक्रिया के कारण और भी बढ़ जाती है।
- **NARCL** की चुनौतियों के लिये संभावित समाधान:
    - **IDRCL** व **NARCL** के संयोजन से संचालन सुव्यवस्थित हो सकता है, लागत कम हो सकती है और दोहराव वाले कार्यों को समाप्त करके दक्षता बढ़ सकती है।
    - प्रदर्शन-लिंक्ड प्रोत्साहनों को लागू करने से कुशल पेशेवर आकर्षित हो सकते हैं और परिसंपत्ति रेज़ॉल्यूशन की प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है।
    - परिसंपत्ति रेज़ॉल्यूशन में घरेलू और विदेशी निवेशकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिये निवेशक-अनुकूल नीतियाँ।
    - चलनिधि और मूल्य निर्धारण में सुधार के लिये आपात परिसंपत्तियों के लिये द्वितीयक बाज़ार को बढ़ावा देना।

## स्विस चैलेंज विधि

- स्विस चैलेंज विधि एक सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया है जो निजी कंपनियों को सरकारी अनुबंधों पर बोली लगाने की अनुमति देती है। इस विधि का प्रयोग सड़क, बंदरगाह और रेलवे जैसी परियोजनाओं या सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिये किया जाता है।
- RBI ने सितंबर 2016 में बैंकों को NPA खातों की बिक्री के लिये स्विस चैलेंज तकनीक का प्रयोग करने की अनुमति दी थी, इसमें शामिल हैं:
    - प्रारंभिक प्रस्ताव: कोई खरीदार NPA खाता खरीदने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
    - प्रति-बोली के लिये आमंत्रण: यदि प्रारंभिक प्रस्ताव नकद में है और बैंक की न्यूनतम सीमा से अधिक है, तो बैंक जवाबी-बोली/प्रति-बोली आमंत्रित करता है।
    - वरीयता क्रम:
        - परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ **(ARC):** बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाली ARC को प्राथमिकता दी जाती है।
        - पहला बोलीदाता: यदि कोई ARC भाग नहीं लेता है, तो प्रारंभिक बोलीदाता को प्राथमिकता दी जाती है।
        - सबसे अधिक बोलीदाता: प्रति-बोली प्रक्रिया के दौरान, सबसे अधिक बोली लगाने वाले का चयन किया जाता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न: 'बैड बैंक' क्या है, और बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के प्रबंधन में इसकी क्या भूमिका है?

https://youtu.be/u_SSox2FjVU?si=5sEHLqZ5dOATL5pl

**UPSC** सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न **(PYQ)**

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: **(2018)**

1. पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूँजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

**(a)** केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो **1,** न ही **2**

उत्तर: **(b)**

व्याख्या:

- सरकार ने क्रेडिट विस्तार का समर्थन करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के लिये किये जाने वाले प्रावधानों से होने वाले नुकसान से निपटने में मदद हेतु राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में पूंजी अंतर्वेशन का कार्य किया है।
- परंतु सरकारी बैंकों में पूंजी अंतर्वेशन का चलन किसी एक दिशा में विशिष्ट नहीं रहा है, यह घटता-बढ़ता रहा है। अतः कथन **1** सही नहीं है।
- फरवरी 2017 में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भारतीय महिला बैंक और पाँच सहयोगी बैंकों के विलय को मंज़ूरी दी थी। विलय का उद्देश्य सार्वजनिक बैंक संसाधनों का युक्तिकरण, लागत में कमी, बेहतर लाभप्रदता और जनता के लिये ब्याज की बेहतर दर के लिये धन की कम लागत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उत्पादकता एवं ग्राहक सेवा में सुधार करना था। संसद ने सार्वजनिक बैंक के युक्तिकरण को प्रभावित करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक के साथ छह सहायक बैंकों का विलय करने हेतु स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया। अतः कथन **2** सही है।

अतः विकल्प **(b)** सही है।

मेटा सर्च की-वर्ड्स: National Asset Reconstruction Company Ltd, NARCL, Government-Backed Bad Bank, Stressed Assets Acquisition, Non-Performing Assets, Bad Banks, Asset Reconstruction Companies, NARCL Targets FY26, IDRCL Role, Bad Asset Management, Swiss Challenge Method, Pricing Bad Loans, Swiss Challenge Technique, Financial Stability, Asset Resolution, Public Sector Banks, Government-Backed Loans, Investor Policies for Distressed Assets, UPSC CSE, PYQ, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एनएआरसीएल, सरकार समर्थित बैड बैंक, दबावग्रस्त परिसंपत्ति अधिग्रहण, गैर-निष्पादित संपत्ति, बैड बैंक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ, एनएआरसीएल का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26, आईडीआरसीएल की भूमिका, बैड एसेट मैनेजमेंट, स्विस चैलेंज विधि, बैड लोन का मूल्य निर्धारण, स्विस चैलेंज तकनीक, वित्तीय स्थिरता, एसेट रेज़ॉल्यूशन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकार समर्थित ऋण, आपात परिसंपत्तियों के लिये निवेशक नीतियाँ, यूपीएससी सीएसई, विगत वर्ष के प्रश्न।

संक्षिप्त विवरण: सरकार समर्थित बैड बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025- 26 तक 2 ट्रिलियन रुपए की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना है। वित्त वर्ष 2024-25 में 1 ट्रिलियन रुपए की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने में कंपनी की सफलता के बाद यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पी टैग: रैपिड फायर
एस टैग: रैपिड फायर करेंट अफेयर, प्रारंभिक परीक्षा, विविध

# Kasturi Cotton Bharat Initiative

# कस्तूरी कॉटन भारत पहल

स्रोत : पी.आई.बी

कपड़ा मंत्रालय का कस्तूरी कॉटन भारत कार्यक्रम भारतीय कपास की ट्रेसबिलिटी, प्रमाणन और ब्रांडिंग में एक अग्रणी प्रयास है।

- यह कॉटन की ट्रेसबिलिटी और प्रमाणन को बढ़ाने के लिये भारत सरकार (कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया), व्यापार निकायों और उद्योगों के बीच एक सहयोग है।
- एंड-टू-एंड ट्रेसबिलिटी और लेनदेन प्रमाणन के लिये क्यूआर कोड सत्यापन और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म वाली एक माइक्रोसाइट विकसित की गई है।
- कार्यक्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें राज्य-विशिष्ट के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर धन आवंटित किया जाता है।
- लगभग **343** आधुनिकीकृत जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयाँ पंजीकृत हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश की 15 इकाइयाँ शामिल हैं।
    - आंध्र प्रदेश से लगभग 100 गाँठों को कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड के तहत प्रमाणित किया गया है।
- भारत में कॉटन (कपास) एक महत्त्वपूर्ण फसल है, जो वैश्विक उत्पादन में **25%** का योगदान देती है और अपने आर्थिक मूल्य के लिये इसे "व्हाइट-गोल्ड" के रूप में जाना जाता है। यह गर्म, धूप वाले मौसम और विभिन्न प्रकार की मृदा में पनपती है, लेकिन जलभराव के प्रति संवेदनशील होती है।

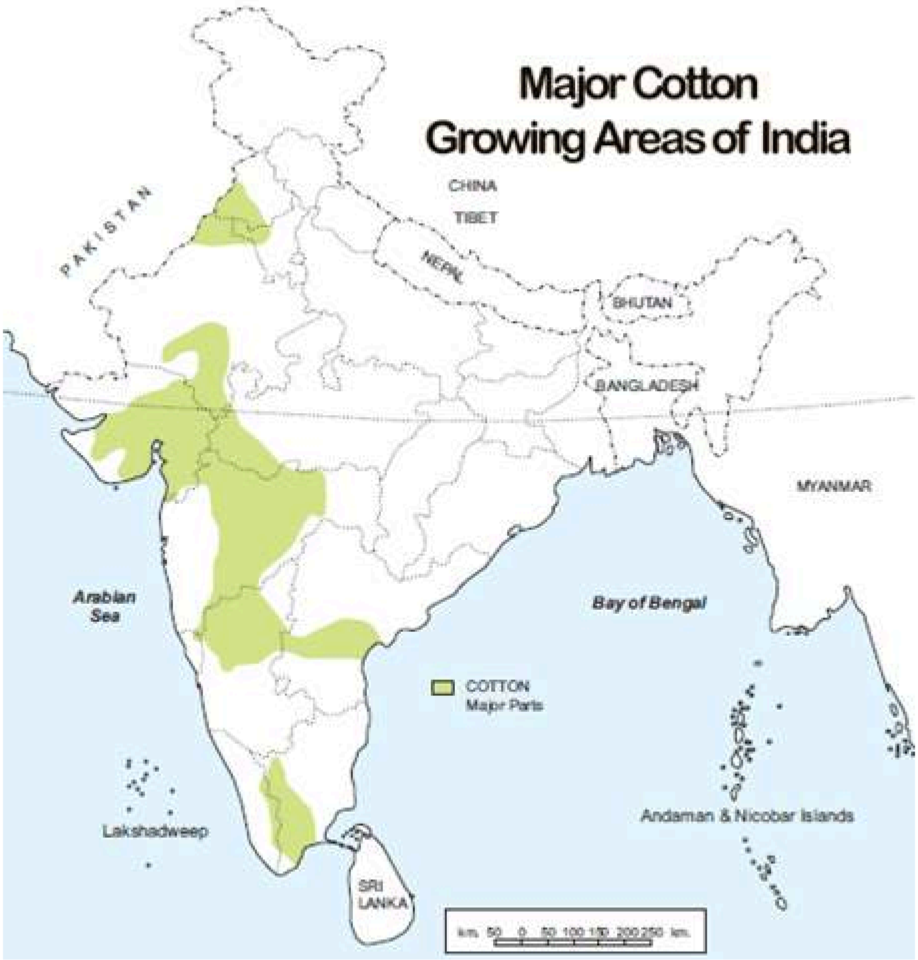


और पढ़ें: कस्तूरी कॉटन द्वारा भारत के कॉटन सेक्टर को बढ़ावा, भारत में कॉटन उत्पादन

कीवर्ड: Kasturi Cotton Bharat, certification, blockchain technology, QR codes, Ministry of Textiles, Cotton Corporation of India, Cotton Textiles Export Promotion Council, Andhra Pradesh, ginning units, UPSC, CSE, PYQ.कस्तूरी कॉटन भारत, प्रमाणन, ब्लॉकचेन तकनीक, क्यूआर कोड, कपड़ा मंत्रालय, भारतीय कॉटन निगम, कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आंध्र प्रदेश, जिनिंग यूनिट, यूपीएससी, सीएसई, विगत वर्ष के प्रश्न।
विवरण: कस्तूरी कॉटन भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संचालित होता है, जिसका उद्देश्य भारतीय कपास को बढ़ावा देना है। यह व्यापक ट्रेसेबिलिटी के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है, जिससे भारतीय कॉटन मूल्य शृंखला में हितधारकों को लाभ मिलता है।

---

पी टैग: भारतीय अर्थव्यवस्था
एस टैग: सामान्य अध्ययन- 1, सामान्य अध्ययन- 2, सामान्य अध्ययन- 3, शहरीकरण, विकास से संबंधित मुद्दे, बुनियादी ढाँचा

# Transit-Oriented Urban Development

# पारगमन-उन्मुख शहरी विकास

**प्रिलिम्स के लिये:** पारगमन उन्मुख विकास (TOD), विकास केंद्र, पेरी-शहरी क्षेत्र, भूमि उपयोग, बाजार संभावित मूल्य, सार्वजनिक पारगमन, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, आपदा लचीलापन, राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (TOD) नीति, 2017, शहरी बुनियादी ढाँचा विकास निधि (UIDF)
**मेन्स के लिये:** शहरी क्षेत्रों के सतत् कामकाज में पारगमन उन्मुख विकास की भूमिका।
स्रोत: द हिंदू

## चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिये पारगमन उन्मुख विकास **(Transit-Oriented Development- TOD)** योजना का प्रस्ताव रखा।

- आर्थिक और पारगमन योजना तथा पेरी-अर्बन क्षेत्रों (शहर के आसपास के क्षेत्र) के व्यवस्थित विकास के माध्यम से शहरों को "विकास केंद्रों" के रूप में विकसित किया जाएगा।

## पारगमन उन्मुख विकास (TOD) क्या है?

- परिचय:
    - TOD एक योजना रणनीति है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के आसपास नौकरियों, आवास और सेवाओं को केंद्रित करना है।
        - यह ऐसे विकास को प्रोत्साहित करता है जहाँ पैदल या बाइक से जाना आसान हो, तथा नौकरियाँ, घर और सेवाएँ परिवहन विकल्पों के निकट स्थित हों।
    - TOD इस विचार पर काम करता है कि आर्थिक विकास, शहरी परिवहन और भूमि उपयोग को एक साथ नियोजित करने पर वे अधिक कुशल होते हैं।
    - इस दृष्टिकोण का उपयोग स्टॉकहोम, कोपेनहेगन, हॉन्गकॉन्ग, टोक्यो और सिंगापुर जैसे शहरों में सफलतापूर्वक किया गया है।
- विश्व बैंक **3V** फ्रेमवर्क **TOD** योजनाओं का मार्गदर्शन करता है:
    - नोड मूल्य: यह यात्री यातायात, अन्य परिवहन साधनों के साथ कनेक्शन और नेटवर्क के भीतर केंद्रीयता के आधार पर सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में किसी स्टेशन के महत्व का वर्णन करता है।
    - स्थानीय मान: यह स्टेशन के आसपास के क्षेत्र की गुणवत्ता और आकर्षण को दर्शाता है।
        - प्रमुख कारकों में विविध भूमि उपयोग, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच, पैदल या साइकिल दूरी के भीतर सुविधाओं की उपलब्धता, पैदल यात्री-अनुकूल डिज़ाइन तथा स्टेशन के आसपास शहरी ब्लॉकों का आकार शामिल हैं।
    - बाज़ार संभावित मूल्य: यह स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों के संभावित बाजार मूल्य को संदर्भित करता है।
        - इसका आकलन आस-पास की वर्तमान और भविष्य की नौकरियों की संख्या, 30 मिनट के भीतर परिवहन द्वारा उपलब्ध नौकरियों की संख्या, आवास घनत्व, विकास के लिये उपलब्ध भूमि, संभावित क्षेत्र परिवर्तन तथा समग्र बाज़ार गतिविधि जैसे कारकों पर विचार करके किया जाता है।

Synchronization of Node, Place, and Market Potential Values

- 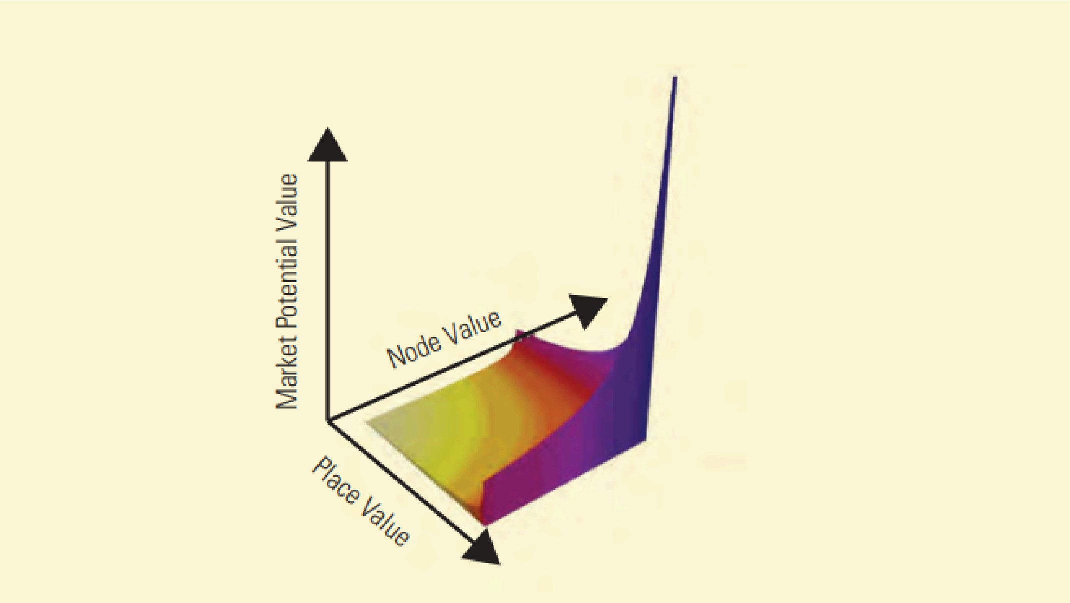


- **TOD के लाभ:**
  - आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना: TOD अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहरों को योजनाबद्ध तरीके से धारणीय शहरी विकास केंद्रों के रूप में विकसित करता है और छोटे क्षेत्रों में नौकरियों का समूह बनाता है, जिससे शहर की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि जैसे लाभ होते हैं।
    - शोध से पता चलता है कि नौकरी घनत्व को दोगुना करने से आर्थिक उत्पादकता **5** से **10%** तक बढ़ सकती है।
  - जीवंत और रहने योग्य समुदाय: TOD नौकरियों, आवास और सुविधाओं को पारगमन स्टेशनों के करीब लाता है, शानदार सार्वजनिक स्थानों और कम यात्रा दूरी के साथ जीवंत समुदायों का निर्माण करता है, जिससे शहर अधिक रहने योग्य बनते हैं।
  - कॉम्पैक्ट शहरी विकास और सार्वजनिक परिवहन का पारस्परिक सुदृढ़ीकरण: कॉम्पैक्ट शहरी विकास और अच्छा सार्वजनिक परिवहन एक साथ काम करते हैं। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र अधिक यात्रियों को लाते हैं, जिससे परिवहन प्रणाली लाभदायक बनती है, जबकि स्टेशनों के पास नौकरियों और आवासों का संकेन्द्रण इन परिवहन प्रणालियों का समर्थन करता है।
  - अचल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि: जन परिवहन के निकट होने के कारण TOD क्षेत्र अधिक आकर्षक बन जाते हैं, जिससे अचल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है।
    - शहर इस अतिरिक्त मूल्य का उपयोग परिवहन उन्नयन, किफ़ायती आवास और सतत् विकास के लिये कर सकते हैं।
    - हॉन्गकॉन्ग में इस दृष्टिकोण से वर्ष 1980 और 2005 के बीच 140 बिलियन हांगकांग डॉलर जुटाए गए तथा 6,00,000 सार्वजनिक आवास इकाइयों के लिये भूमि उपलब्ध कराई गई।
  - समावेशिता को बढ़ावा देना: यद्यपि **TOD** संपत्ति की कीमतों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन नए विकास में किफ़ायती आवास को शामिल करके इसे कम किया जा सकता है।
    - समावेशी **TOD** दृष्टिकोण सभी आय स्तर के लोगों के लिये नौकरियों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
  - कार्बन फुटप्रिंट में कमी: TOD से कार का उपयोग कम होता है, यात्रा का समय कम होता है, उत्पादकता बढ़ती है, तथा कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

        - उदाहरण के लिये स्टॉकहोम में पारगमन मार्गों का विकास होने से प्रति व्यक्ति आर्थिक मूल्य में 41% की वृद्धि हुई तथा वर्ष 1993 से 2010 तक प्रति व्यक्ति [ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन] में 35% की कमी आई।
    - आपदा लचीलेपन को समर्थन प्रदान करना: जब प्राकृतिक आपदाओं के प्रति कम संवेदनशील क्षेत्रों में इसे क्रियान्वित किया जाता है, तो TOD सुरक्षित क्षेत्रों में उच्च घनत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करके आपदा लचीलेपन को बढ़ा सकता है, जिससे जोखिमों का जोखिम कम हो जाता है।

- 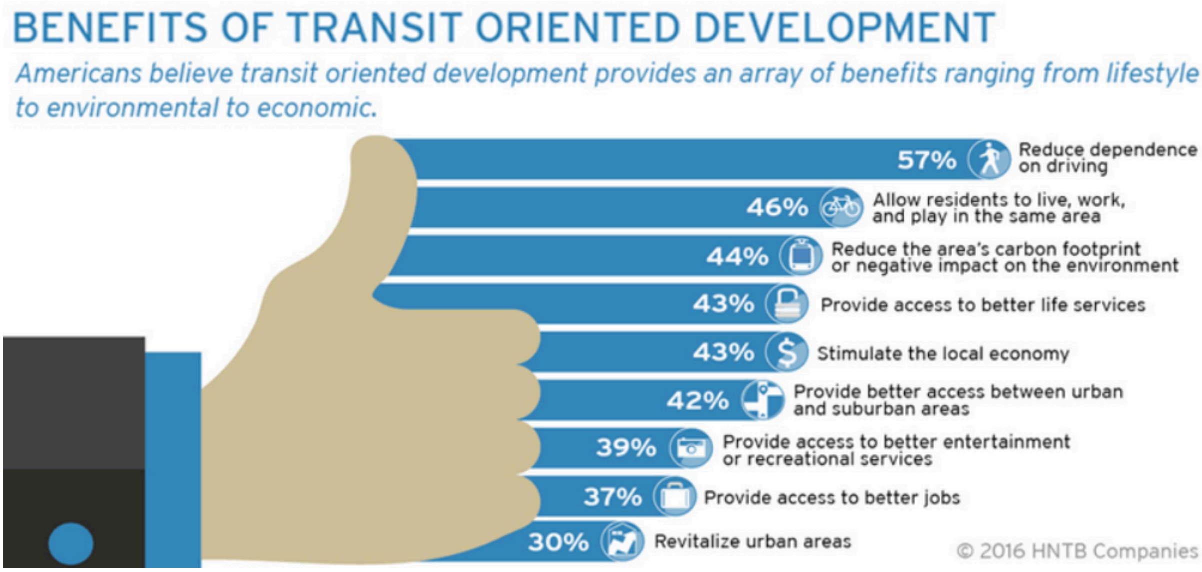


- TOD की मांग को बढ़ाने वाले कारक:
    - तेज़ी से बढ़ती यातायात भीड़: राष्ट्रव्यापी यातायात भीड़ तेज़ी से बढ़ रही है और अत्यधिक होती जा रही है, जिससे अधिक कुशल शहरी नियोजन की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है।
    - उपनगरीय क्षेत्रों के प्रति असंतोष: उपनगरीय क्षेत्रों के विस्तार और पट्टी विकास के प्रति असंतोष बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग विकल्प तलाश रहे हैं।
    - गुणवत्तापूर्ण शहरी जीवनशैली की इच्छा: अधिक लोग उच्च गुणवत्ता वाली शहरी जीवनशैली की चाहत रखते हैं, जो बेहतर सुविधाएँ और अनुभव प्रदान करती हो।
    - पैदल चलने योग्य वातावरण को प्राथमिकता: अधिक पैदल चलने योग्य जीवनशैली की इच्छा बढ़ रही है, जो भारी यातायात से मुक्त हो, तथा दैनिक सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाए।
    - पारिवारिक संरचना में परिवर्तन: एकल-व्यक्ति परिवारों और खाली-घोंसले वालों (जिनके वयस्क बच्चे घर छोड़ चुके हैं) की संख्या में वृद्धि से शहरी जीवन विकल्पों की मांग प्रभावित हो रही है।
    - स्मार्ट विकास के लिये समर्थन: स्मार्ट विकास सिद्धांतों हेतु राष्ट्रीय समर्थन बढ़ रहा है, जो सतत् और कुशल भूमि उपयोग पर जोर देते हैं।
- TOD के घटक:
    - पैदल चलने योग्य डिज़ाइन: इसमें पैदल चलने पर मुख्य ध्यान देते हुए पैदल यात्री अनुकूल डिज़ाइन को प्राथमिकता दी गई है।
    - क्षेत्रीय नोड: इसमें एक क्षेत्रीय नोड में उपयोगों का मिश्रण शामिल होता है, जैसे कार्यालय स्थान, आवासीय क्षेत्र, खुदरा और नागरिक सुविधाएँ, सभी एक दूसरे के निकट होते हैं।
    - कलेक्टर ट्रांजिट सिस्टम: इसमें स्ट्रीटकार, लाइट रेल और बस जैसी सहायक ट्रांजिट प्रणालियाँ शामिल हैं।
        - दैनिक परिवहन विकल्प के रूप में साइकिल और स्कूटर के आसान उपयोग के लिये डिज़ाइन किया गया।

    - प्रबंधित पार्किंग: पार्किंग की व्यवस्था कम कर दी गई है तथा शहर के केंद्र और रेलवे स्टेशन के चारों ओर 10 मिनट की पैदल दूरी के भीतर इसका प्रबंधन किया गया है।
    - विशिष्ट खुदरा: स्टेशनों पर यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिये कैफे, किराना स्टोर और ड्राई क्लीनर जैसी विशिष्ट खुदरा सेवाएँ उपलब्ध हैं।

## TOD से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- महानगर स्तर पर क्षेत्रीय समन्वय का अभाव: भारत के महानगरीय क्षेत्रों में प्रायः अलग-अलग एजेंडे वाले कई नगरपालिका और राज्य प्राधिकरण होते हैं, जिसके कारण TOD नियोजन खंडित हो जाता है।
- समावेशी नहीं: भूमि उपयोग और परिवहन के लिये अलग-अलग नियोजन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप असंगत लक्ष्य एवं अकुशल TOD विकास हो सकता है।
    - इसके अलावा इसमें कृषि और संबद्ध सेवाओं जैसे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में नहीं रखा गया है।
- उच्च जनसंख्या घनत्व: अपर्याप्त विनियमन के परिणामस्वरूप या तो कुछ क्षेत्रों में विकास का अत्यधिक संकेंद्रण हो सकता है या अन्य क्षेत्रों में कम प्रयोग हो सकता है।
    - इससे उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना पर दबाव पड़ सकता है, जबकि शहर के अन्य हिस्से अविकसित और अपर्याप्त संपर्क वाले रह जाएंगे।
- उपेक्षित शहरी डिज़ाइन: कई भारतीय शहरों में अच्छी तरह से डिज़ाइन किये गए फुटपाथ, क्रॉसवॉक और पैदल यात्री क्षेत्र की कमी है, जिससे सुरक्षित व आराम से ट्रांज़िट स्टेशनों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इससे पैदल चलने वालों को खतरनाक और भीड़भाड़ वाले रास्तों से यात्रा करने के लिये मज़बूर होना पड़ेगा।
- भारतीय शहरों के लिये अनुपयुक्त: हॉन्गकॉन्ग और सिंगापुर जैसे द्वीपीय शहरों में TOD भूमि प्रयोग दक्षता को अधिकतम करता है, जिससे अधिक लोगों को पारगमन क्षेत्र के निकट रहने और कार्य करने की अनुमति मिलती है, जिससे व्यापक विकास की आवश्यकता कम हो जाती है। यह नई दिल्ली या बेंगलुरु जैसे भारतीय शहरों के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- लोगों के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं: ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने के लिये निजी वाहनों के उपयोग को कम करने में व्यवहार परिवर्तन एक महत्त्वपूर्ण कारक है। अकुशल सार्वजनिक परिवहन तंत्रों में भारी निवेश के बावजूद TOD लोगों को निजी वाहन का उपयोग कम करने के लिये प्रेरित नहीं कर सकता है।
- आपदा के प्रति अधिक संवेदनशीलता: एक छोटे से क्षेत्र में लोगों की भीड़भाड़ से आपदा के दौरान हताहतों और घायलों की संभावना बढ़ जाती है। सड़कों, उपयोगिताओं और आपातकालीन सेवाओं जैसे अत्यधिक बोझ वाली बुनियादी अवसंरचना के कारण आपदा के दौरान यह जल्दी ही अभिभूत हो सकता है।
- शहरी प्रसार: तेज़ी से शहरीकरण के कारण शहरों का विस्तार हो रहा है, जिससे कॉम्पैक्ट वॉकेबल पड़ोस बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिये अहमदाबाद जैसे शहरों में काफी प्रसार है, जिससे TOD सिद्धांतों के क्रियान्वयन में जटिलता आ रही है।
- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: यह सुनिश्चित करना कि TOD से सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों को लाभ मिले, यह महत्त्वपूर्ण है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। इस बात का जोखिम है कि नए विकास मुख्य रूप से निम्न-आय वाले निवासियों को छोड़कर समृद्ध आबादी के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।
- अन्य मुद्दे: विनियामक, सामुदायिक और वित्तीय चुनौतियाँ बेंगलुरु, चेन्नई व कोलकाता जैसे भारतीय शहरों में TOD में बाधा डालती हैं। ज़ोनिंग कानून, सामुदायिक प्रतिरोध और बजट की कमी मिश्रित-उपयोग विकास तथा पारगमन सुधारों को सीमित करती है।

## राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (TOD) नीति, 2017

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय **(MoHUA)** ने राष्ट्रीय पारगमन-उन्मुख विकास नीति **2017** शुरू की। इसे शहरी विकास के लिए पारगमन उन्मुख विकास **(TOD)** का उपयोग करने में राज्यों और शहरों की सहायता करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- विज़न:
  - परिवर्तन: निजी वाहन पर निर्भरता से सार्वजनिक परिवहन-उन्मुख विकास की ओर बदलाव।
  - पहुँच: सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना।
  - पैदल चलने योग्य समुदाय: कॉम्पैक्ट, किफ़ायती और पैदल चलने योग्य वातावरण विकसित करना।
  - सार्वजनिक परिवहन: पारगमन और पैदल यात्राएँ बढ़ाना, प्रदूषण और भीड़भाड़ को कम करना।
  - सघन अवसंरचना: सघन सड़क नेटवर्क बनाना  और निजी वाहन स्वामित्व को कम करना।
  - समावेशी आवास: किफायती और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये आवास शामिल करना।
  - मनोरंजन और सुरक्षा: विशेष रूप से कमज़ोर समूहों के लिये मनोरंजक स्थान और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - पर्यावरणीय प्रभाव: पर्यावरण के अनुकूल यात्रा विकल्पों को बढ़ावा देकर कार्बन पदचिह्नों को कम करना।

## भारत में पारगमन उन्मुख शहरी विकास के लिये की गई पहल

- राष्ट्रीय **TOD** नीति **2017**
- मेट्रो रेल नीति **2017**
- शहरी अवसंरचना विकास निधि **(UIDF)**
- मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब **(MMTH)**

## निष्कर्ष

ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) एक आधुनिक शहरी नियोजन दृष्टिकोण है जो उच्च घनत्व, मिश्रित-उपयोग वाले वातावरण को बढ़ावा देने के लिये भूमि उपयोग को ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य वाहनों पर निर्भरता को कम करना, भीड़भाड़ को कम करना और स्थिरता को बढ़ाना है। सफल TOD समन्वय, ऊर्ध्वगामी विकास और बेहतर कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है, जिसे भारत में अपनाया जा रहा है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न*:*
प्रश्न: चर्चा कीजिये कि ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) शहरों के सतत् विकास में कैसे एक गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है। भारतीय शहरों के लिये TOD के साथ क्या चुनौतियाँ आती हैं?

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न **(PYQs)**
मेन्स

प्रश्न. भारत में तीव्र आर्थिक विकास के लिये कुशल और किफ़ायती शहरी जन परिवहन कैसे महत्त्वपूर्ण है? (2019)
प्रश्न. भारत में शहरी जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, 'स्मार्ट सिटी कार्यक्रम' के उद्देश्यों और रणनीति का परिचय दीजिये। (2016)

कीवर्ड**:** Transit Oriented Development (TOD), Growth Hubs, Peri-Urban Areas, Land Use, Node Value, Place Value, Market Potential Value, Public Transit, Greenhouse Gas Emissions, Disaster Resilience, Suburban, National Transit Oriented Development (TOD) Policy, 2017, Urban Infrastructure Development Fund (UIDF), UPSC, CSE, PYQ. ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD), ग्रोथ हब, पेरी-अर्बन एरिया, लैंड यूज़, नोड वैल्यू, प्लेस वैल्यू, मार्केट पोटेंशियल वैल्यू, पब्लिक ट्रांजिट, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, आपदा लचीलापन, उपनगरीय, राष्ट्रीय ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति, 2017, शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF), यूपीएससी, सीएसई, विगत वर्ष के प्रश्न .
विवरण: केंद्र सरकार ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिये ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) योजना प्रस्तावित की।